भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **177**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 02 फरवरी, 2024/13 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों के लिए बजट परिव्यय

177. श्री नलीन कुमार कटील:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में उर्वरकों के लिए बजट परिव्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा मृदा की उर्वरता को बेहतर बनाए रखने के लिए अजैविक और जैविक उर्वरकों के संतुलित और समेकित उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है जिसके परिणामस्वरूप देश में उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार देश में उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में किसानों के प्रशिक्षण, किसानों के खेतों पर प्रदर्शन करने और किसान मेलों के आयोजन के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क): विगत तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक) के दौरान देश में उर्वरकों के लिए बजट परिव्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	**राशि (करोड़ में)**
2021-22	162072.1
2022-23	254798.9
2023-24	201121

(ख): आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 28 जून, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में "धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)" को अनुमोदित किया है। इस पहल का उद्देश्य उर्वरकों के सतत तथा संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने, आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के माध्यम से धरती माता के स्वास्थ्य को बचाने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा शुरू किए गए प्रयासों को समर्थन प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने, नैनो/जैव/ऑर्गेनिक उर्वरकों आदि जैसे वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग आदि के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके साथ ही, पीएम-प्रणाम स्कीम के संवर्द्धन को विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) की गतिविधियों में से एक के रूप में शामिल किया गया है, जिसे 15 नवम्बर, 2023 को शुरू किया गया है। उर्वरक विभाग विभिन्न मंचों के माध्यम से स्कीम को बढ़ावा भी दे रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण प्रयोग तथा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने हेतु 4आर दृष्टिकोण अर्थात उर्वरकों की राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, राइट मोड और राइट टाइप के साथ पादप पोषकतत्वों के इनऑर्गेनिक तथा ऑर्गेनिक (खाद, जैव-उर्वरक, हरी खाद, स्वस्थाने फसल अवशेष पुनर्चक्रण आदि) दोनों स्रोतों के मिले-जुले उपयोग के जरिये मृदा परीक्षण आधारित संतुलित एवं एकीकृत पोषकतत्व प्रबंधन की सिफारिश भी करता है।

(ग) और (घ): सरकार लद्दाख सहित पूरे देश में सॉइल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) लागू कर रही है। इस स्कीम के तहत, वर्ष 2014-15 से अब तक 23.74 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं तथा देश में उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने हेतु, किसानों के खेतों में प्रदर्शन एवं कृषक मेला आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) की सिफारिशों के आधार पर ऑर्गेनिक खाद एवं जैव उर्वरकों के संयोजन में द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषकतत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर सिफारिशों को अपनाए जाने के लिए किसानों के बीच जागरुकता फैलाने के लिए प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनियां आयोजित की जाती है। देश भर में अब तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड सिफारिशों पर 93781 किसानों को प्रशिक्षण, 6.45 लाख प्रदर्शनियां, 7425 किसान मेला/अभियान आयोजित किए गए हैं।

******